नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 182
दि. 06.04.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कूचबिहार से उठी बदलाव की गूंज, बंगाल की सियासत में तेज हुआ संग्राम

कोलकाता/कूचबिहार। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में कूचबिहार की रैली ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। Narendra Modi ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि राज्य में अब बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी बदल सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ही इस बात से की कि कूचबिहार की रैली में उमड़ी भीड़ अपने आप में यह संदेश दे रही है कि जनता का भरोसा अब बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से शुरू हुआ अभियान अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है और इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, राज्य में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और यह असंतोष अब बदलाव की मांग में बदल चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि जनता की भावना है जो अब खुलकर सामने आ रही है।

Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था ने आम लोगों का जीवन प्रभावित किया है। उन्होंने "सिंडिकेट राज" और "कटमनी संस्कृति" जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि इन कारणों से विकास की गति बाधित हुई है और आम नागरिकों को अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इन व्यवस्थाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य में वास्तविक विकास संभव नहीं है।

घुसपैठ का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के भाषण का एक अहम हिस्सा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ ने न केवल सुरक्षा को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन को भी बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो इस समस्या से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है, जो चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि चुनाव के बाद "हिसाब" होगा और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सत्ता परिवर्तन के बाद जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहा है, लेकिन समर्थकों के लिए यह एक मजबूत नेतृत्व का संकेत है।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने संदेशखाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 33 प्रतिशत आरक्षण कानून का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेगा। यह मुद्दा खास तौर पर महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानून-व्यवस्था और तुष्टिकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ है और इससे अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की नीति के कारण राज्य की पहचान और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिले।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य हमेशा से ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बदलाव के लिए आगे आएं और राज्य को एक नई दिशा देने में भागीदारी निभाएं। उनका यह संदेश केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक अपील के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने बंगाल की गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने की बात कही।

कुल मिलाकर, कूचबिहार की यह रैली पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री ने आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी, वहीं दूसरी ओर इसने यह संकेत भी दिया कि आने वाले चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धी और निर्णायक होने वाले हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस राजनीतिक विमर्श को किस दिशा में ले जाती है और क्या वास्तव में बंगाल में वह बदलाव आता है, जिसकी चर्चा इस समय हर मंच पर हो रही है।

पंजाब की सेहत क्रांति: हर परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज का भरोसा

नई दिल्ली। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' आम लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हो रही है। Bhagwant Mann के नेतृत्व में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य हर परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी के दौरान इलाज के खर्च की चिंता लोगों को न सताए। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनकी जिंदगी में स्थिरता आई है।

पंजाब जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी मध्यम और निम्न आय वर्ग से आती है, वहां महंगे इलाज का खर्च अक्सर परिवारों को कर्ज में डुबो देता था। कई बार लोग केवल पैसे की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते थे, जिससे छोटी बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती थी। लेकिन 'सेहत योजना' ने इस स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है। अब लोग बिना किसी डर के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2300 से अधिक बीमारियों को कवर किया गया है। इसमें दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी से जुड़ी समस्याएं, डायलिसिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और जन्म से जुड़ी जटिलताओं जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। ये वही बीमारियां हैं, जिनका इलाज आमतौर पर बेहद महंगा होता है और जिनके कारण परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। लेकिन अब इस योजना के कारण मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल पा रहा है, जिससे उनकी जान बचाने की संभावना भी बढ़ गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 33 लाख से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और लगातार इसकी पहुंच बढ़ रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक करीब 1.98 लाख इलाजों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिन पर 330 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो रही है और लोगों को वास्तविक लाभ दे रही है।

डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि मरीज अब इलाज में देरी नहीं करते। पहले जहां लोग खर्च के डर से अस्पताल जाने में हिचकिचाते थे, वहीं अब वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करते हैं और समय रहते इलाज शुरू हो जाता है। खासकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गंभीर संक्रमण जैसे मामलों में समय पर इलाज मिलना जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क साबित होता है। इस योजना ने इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, इस योजना ने निजी अस्पतालों को भी स्वास्थ्य सेवा के इस मिशन में शामिल किया है। पहले जहां निजी अस्पतालों का इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर था, वहीं अब इस योजना के तहत वहां भी मुफ्त या सब्सिडी वाला इलाज संभव हो पाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आया है और मरीजों को बेहतर विकल्प मिल रहे हैं।

सरकार केवल योजना को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके विस्तार और सुधार पर भी लगातार काम कर रही है। नए अस्पतालों को नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है, तकनीकी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित होती है। वहां मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और कैंप के जरिए लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य सेवा किसी भी समाज का मूल अधिकार होना चाहिए, लेकिन अक्सर आर्थिक असमानता के कारण यह सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती। 'सेहत योजना' इस अंतर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि गरीब और अमीर दोनों को समान स्तर की चिकित्सा सुविधा मिल सके।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा टकराव, दुनिया पर मंडराया ऊर्जा संकट का खतरा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है, जहां Donald Trump की ताजा चेतावनी ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि यदि Iran होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तो 7 अप्रैल से उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच टकराव नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह संदेश दिया कि ईरान को पहले ही 10 दिन की समयसीमा दी गई थी, जो अब समाप्त होने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो "गंभीर परिणाम" भुगतने होंगे। इस संभावित कार्रवाई में बिजली संयंत्र, पुल, तेल प्रतिष्ठान और जल आपूर्ति से जुड़े ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। यह रणनीति केवल सैन्य दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि ईरान की आंतरिक व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से भी देखी जा रही है।

हालिया घटनाक्रम इस तनाव को और स्पष्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और Israel की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के करज क्षेत्र में एक बड़े पुल को निशाना बनाया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस हमले को आने वाले बड़े सैन्य अभियान का संकेत माना जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि कूटनीतिक प्रयासों के विफल होने के बाद अब सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

ईरान ने इन धमकियों का कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह के हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत "युद्ध अपराध" की श्रेणी में आएंगे। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाती है, तो उसका जवाब दिया जाएगा और क्षेत्र में मौजूद रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि स्थिति किसी भी समय बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है।

Strait of Hormuz का महत्व इस पूरे विवाद को और गंभीर बना देता है। यह संकरा समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, और दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि इस मार्ग पर किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खास तौर पर भारत, चीन, जापान और यूरोपीय देशों के लिए यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज पर बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है। एक ओर अमेरिका अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखना चाहता है, वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच, इजराइल की भूमिका भी अहम हो जाती है, जो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता है।

कूटनीतिक स्तर पर भी कई प्रयास किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह आशंका बढ़ रही है कि यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो यह विवाद एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस स्थिति का प्रभाव पहले ही दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, खासकर उन देशों के लिए जो पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता यह टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हर फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप की सख्त चेतावनी, ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय अस्थिरता मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा कर रहे हैं।

असम चुनाव से पहले पासपोर्ट विवाद ने बढ़ाई सियासी तल्खी

दिसपुर। असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले राज्य की राजनीति में एक नया विवाद उभरकर सामने आया है, जिसने सियासी माहौल को और अधिक गरमा दिया है। Pawan Khera द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद Himanta Biswa Sarma और उनकी पत्नी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल चुनावी विमर्श का केंद्र बदल दिया है, बल्कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के स्तर तक बहस को पहुंचा दिया है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी सरमा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। इसके साथ ही खेड़ा ने यह भी कहा कि दुबई में उनकी संपत्तियां हैं और अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक बड़ी कंपनी से उनका संबंध है। इन आरोपों के जरिए उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या रिंकी सरमा के पास भारतीय नागरिकता भी है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। खेड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

इन आरोपों के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और इसे पारदर्शिता तथा जवाबदेही से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि, सत्तारूढ़ पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे चुनावी साजिश करार दिया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण अभियान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जनता का समर्थन उनके पक्ष में बढ़ रहा है, विपक्ष घबराहट में इस तरह के निराधार आरोप लगा रहा है। सरमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सभी दावे मनगढ़ंत हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे और उनकी पत्नी पवन खेड़ा के खिलाफ 48 घंटे के भीतर आपराधिक और दीवानी मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। यह बयान इस बात का संकेत है कि मामला अब केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप भी ले सकता है। इससे आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, जैसे नाम और तस्वीर का मेल न खाना, तारीखों में विसंगति और क्यूआर कोड में त्रुटियां। उन्होंने दावा किया कि ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं और इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए तैयार किया गया है।

इस पूरे विवाद ने असम की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर विपक्ष इस मुद्दे को पारदर्शिता और नैतिकता से जोड़कर पेश कर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया हमला बता रहा है। चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप आम बात मानी जाती है, लेकिन इस मामले की गंभीरता और व्यक्तिगत प्रकृति ने इसे खास बना दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवाद चुनावी मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इससे जनता का ध्यान विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत आरोपों की ओर चला जाता है। हालांकि, यह भी सच है कि मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो चुके हैं और वे केवल आरोपों के आधार पर अपना निर्णय नहीं लेते।

असम जैसे राज्य में, जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, वहां हर बयान और हर आरोप का असर व्यापक होता है। ऐसे में यह विवाद आने वाले चुनावी परिणामों पर कितना प्रभाव डालता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल, इतना तय है कि इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और अधिक तीखा बना दिया है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी का स्तर और ऊंचा होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, पासपोर्ट और संपत्ति से जुड़े इस विवाद ने असम चुनाव 2026 को एक नया मोड़ दे दिया है। यह केवल एक आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति, छवि निर्माण और जनमत को प्रभावित करने की एक बड़ी कड़ी बन चुका है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मामला कानूनी मोर्चे पर आगे बढ़ता है या फिर चुनावी शोर के बीच धीरे-धीरे दब जाता है।

संपादकीय

फिल्मी कमाई, सामाजिक जिम्मेदारी और चयनात्मक संवेदनाओं का खेल

सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समय-समय पर यह समाज की संवेदनाओं, राजनीति और जनमत को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली औजार बनता गया है। जब कोई फिल्म असाधारण सफलता हासिल करती है और करोड़ों-अरबों की कमाई करती है, तब उसके साथ केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ही नहीं जुड़ते, बल्कि उससे जुड़े सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी उठने लगते हैं। हाल ही में "धुरंधर" जैसी फिल्मों की अपार सफलता के बाद जो चर्चा उठी है, वह इसी व्यापक बहस का हिस्सा है—क्या किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र या पीड़ा को दिखाकर कमाई करने वालों पर उस समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है? ल्यारी के लोगों द्वारा फिल्म की कमाई में हिस्सा मांगना पहली नजर में भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी मानसिकता को समझना जरूरी है। जब कोई फिल्म किसी स्थान, समुदाय या उनके संघर्षों को आधार बनाकर बनाई जाती है और उससे भारी मुनाफा होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस समुदाय के लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनकी कहानी, उनके दर्द का उपयोग किया गया है। ऐसे में वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस कमाई का कुछ हिस्सा उनके विकास या भलाई के लिए भी लगाया जाए। यह मांग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक तरह की मान्यता और सम्मान की भी होती है। इतिहास में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब आर्थिक या राजनीतिक फैसलों ने लंबे समय तक बहस और विवाद को जन्म दिया। बंटवारे के समय पाकिस्तान को दिए गए पचपन करोड़ रुपये आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में यदि किसी फिल्म की कमाई का बड़ा हिस्सा किसी समुदाय को दे दिया जाए, तो यह भी संभव है कि वह घटना आने वाले वर्षों तक चर्चा और आलोचना का विषय बनी रहे। दूसरी ओर, यह भी सच है कि फिल्म निर्माता अपने काम को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। उनके लिए फिल्म बनाना एक निवेश है, जिसमें जोखिम भी होता है और लाभ की उम्मीद भी। ऐसे में वे यह तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने किसी परोपकार या दान के उद्देश्य से फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट के रूप में बनाई है। यदि फिल्म सफल होती है, तो उसका लाभ उनका अधिकार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की अनिवार्य सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा करना उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन समस्या तब जटिल हो जाती है, जब फिल्मों में दिखाए गए विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं—जैसे किसी समुदाय की त्रासदी, ऐतिहासिक अन्याय या सामाजिक उत्पीड़न। "कश्मीर फाइल्स" जैसी फिल्मों के उदाहरण में यह बहस और तीखी हो जाती है कि क्या केवल पीड़ा को दिखाकर मुनाफा कमाना पर्याप्त है, या फिर उस पीड़ा को कम करने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। जब दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और फिल्म को सफल बनाते हैं, तो वे भी यह उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्मकार केवल कमाई तक सीमित न रहें। यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है—चयनात्मक संवेदनाएं। जब एक फिल्म किसी विशेष समुदाय की पीड़ा को दिखाती है और सफल होती है, तो उस पर सामाजिक जिम्मेदारी की बात होती है। लेकिन जब अन्य समुदायों या क्षेत्रों की पीड़ा पर बनी फिल्में असफल हो जाती हैं, तो वही संवेदनाएं गायब हो जाती हैं। "बंगाल फाइल्स" या "केरल फाइल्स" जैसी फिल्मों का न चल पाना इस बात का संकेत है कि दर्शक भी अपनी प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिनेमा और समाज के बीच का रिश्ता सीधा नहीं, बल्कि जटिल और बहुस्तरीय है। असल में, यह पूरा मुद्दा केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच को भी दर्शाता है। हम अक्सर दूसरों की पीड़ा को तब तक महत्व देते हैं, जब तक वह हमारे विचारों या भावनाओं के अनुकूल होती है। जैसे ही वह हमारे दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ मुद्दे राष्ट्रीय बहस बन जाते हैं, जबकि कुछ हाशिए पर ही रह जाते हैं।

एलपीजी का विकल्प बन सकती है बायोगैस

> वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है।

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की क्रांति लाई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती आयात निर्भरता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाल के समय में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। अमेरिका–इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है।

निःसंदेह, यह स्थिति भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को टालना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है—पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और घरेलू रसोई तक प्रभावित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशें। इसी संदर्भ में बायोगैस एक मजबूत और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरती है। बायोगैस जैविक कचरे—जैसे गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कचरा आदि—से उत्पन्न गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में पशुधन और जैविक कचरे की उपलब्धता इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

गांवों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट स्थापित कर स्थानीय स्तर पर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाया जा सकता है, जो एलपीजी और सीएनजी का प्रभावी विकल्प है। 'गोबर-धन योजना' और 'एसएटीएटी' जैसी योजनाएं बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इनके माध्यम से किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस में बदलकर न केवल ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 28–31 मिलियन टन के आसपास है। भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 10–12 एमएमटी प्रति वर्ष है। यानी कुल मांग का केवल 35–40 प्रतिशत ही देश में बनता है। भारत को हर साल लगभग 18–22 एमएमटी एलपीजी आयात करनी पड़ती है। यानी 60–65 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भरता। भारत आधा से ज्यादा एलपीजी बाहर से खरीदता है। आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं।

भारत में अभी लगभग 132 सीबीजी प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 920 टन प्रतिदिन है। यानी अभी बायोगैस का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। भारत 20 एमएमटी सीबीजी बना सकता है। कुल संभावित क्षमता कचरा, गोबर, अवशेष की। कुल क्षमता लगभग 60 एमएमटी तक मानी जाती है। इसका मतलब भारत अपनी पूरी एलपीजी जरूरत (30 एमएमटी) बायोगैस से पूरा कर सकता है। फिलहाल अभी लगभग 300 से अधिक नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत में 2030 तक बायोगैस उत्पादन 7 गुना तक बढ़ सकता है।

बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जैविक खाद भी मिलती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही, यह स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। हालांकि, बायोगैस के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं—जैसे शुरुआती निवेश, तकनीकी जानकारी की कमी और जागरूकता का अभाव। भारत में बायोगैस को लेकर अभी भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे 'गांव की तकनीक' मानते हैं या इसके उपयोग में असुविधा महसूस करते हैं। दूसरी ओर, एलपीजी को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एलपीजी को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएं।

वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है।

आज जरूरत है एक समन्वित प्रयास की—नीतियों, तकनीक और जनभागीदारी के जरिए—ताकि बायोगैस को एलपीजी का वास्तविक विकल्प बनाया जा सके और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

प्रेरणा

अधूरी आवाज़, पूरा विदा

बीस दिन किसी कैलेंडर के पन्नों पर जितने छोटे लगते हैं, जीवन की सच्चाई में उतने ही लंबे और भारी हो जाते हैं, खासकर तब जब हर पल सांसों की गिनती से जुड़ा हो। शर्मा जी के लिए ये बीस दिन केवल समय नहीं थे, बल्कि एक ऐसी यात्रा थे जिसमें उम्मीद, डर, थकान और प्रेम एक साथ चल रहे थे। उनकी मां कोमा में थीं। पहले दिन अस्पताल ले जाते समय उनके मन में विश्वास था कि डॉक्टर, दवाइयां और मशीनें मिलकर चमत्कार कर देंगी। हर रिपोर्ट में, हर जांच में वे कोई संकेत खोजते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे डॉक्टरों की भाषा बदलने लगी। शब्दों में भरोसा कम और औपचारिकता ज्यादा आ गई। अंततः एक दिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया—अब उन्हें घर ले जाइए, जितनी सेवा हो सके, घर पर ही कीजिए।

यह सुनना आसान नहीं था। यह किसी निर्णय की तरह नहीं, बल्कि एक स्वीकार्यता की तरह था—कि अब जो होना है, वह दवाइयों से नहीं, समय से तय होगा। एम्बुलेंस आई। मां को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। शर्मा जी ने उनके चेहरे को गौर से देखा। वह चेहरा जो कभी चिंता, स्नेह और कठोरता के भावों से भरा रहता था, आज बिल्कुल शांत था, जैसे किसी गहरी नींद में हो। उस शांति में एक अजीब-सी दूरी भी थी, जो उन्हें भीतर तक चुभ रही थी।

घर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। अस्पताल की मशीनों की आवाज़ की जगह अब घर की खामोशी थी। वही पुराना कमरा, वही दीवारें, वही खिड़की, जहां से धूप आकर मां के माथे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने एक चक्कर लगाकर खुद को वहीं ला खड़ा किया हो, जहां से सब शुरू हुआ था। दीवार पर टंगी पिता जी की तस्वीर मानो सब कुछ चुपचाप देख रही थी।

शर्मा जी की पत्नी सरला ने बिना कुछ कहे मां का हाथ थाम लिया। उन्होंने धीरे से कहा—"मां, हम आपको घर ले आए हैं।" यह वाक्य केवल सूचना नहीं था, बल्कि एक भरोसा था, जैसे वे यह जताना चाहती हों कि अब आप अपने लोगों के बीच हैं। भले ही जवाब न मिले, लेकिन वे जानती थीं कि सुनने की क्षमता शायद कहीं भीतर अब भी बाकी हो।

दिनचर्या धीरे-धीरे बदल गई। अब हर दिन का केंद्र मां बन गईं। समय पर दवा देना, शरीर की सफाई करना, बिस्तर बदलना, और सबसे महत्वपूर्ण—उनसे बात करते रहना। यह बातचीत एकतरफा थी, लेकिन उसमें भावनाओं की कमी नहीं थी। शर्मा जी अक्सर कुर्सी खींचकर मां के पास बैठ जाते और पुराने दिनों की बातें करने लगते। "मां, याद है जब मैं पहली बार साइकिल से गिरा था, आप कितनी डांट रही थीं और फिर खुद ही मरहम लगा रही थीं।" उनकी आवाज़ में हल्की मुस्कान होती, लेकिन आंखों में नमी छिपी रहती।

रातें सबसे कठिन होती थीं। जब पूरा घर सो जाता, तब खामोशी और गहरी हो जाती। शर्मा जी की आंखों से नींद जैसे दूर चली गई थी। वे मां के पास बैठकर किताब खोल लेते, लेकिन पढ़ते कम और मां की सांसों को ज्यादा सुनते। कभी-कभी उन्हें लगता कि मां की पलकें हल्की-सी हिली हैं या उंगलियों में कोई कंपन हुआ है। हर बार उनका दिल जोर से धड़क उठता—"मां?" लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो जाता, और उन्हें एहसास होता कि शायद यह केवल उनका भ्रम था।

एक दिन वे मां के बाल संवार रहे थे। धीरे-धीरे कंघी करते हुए उन्हें अपना बचपन याद आ गया। जब वे बीमार पड़ते थे, मां पूरी रात जागकर उनके सिरहाने बैठी रहती थीं। ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रहतीं, कभी माथे को सहलातीं, कभी दवा देतीं। उस समय उन्हें लगता था कि यह सब मां का कर्तव्य है, लेकिन आज वही दृश्य उल्टा हो गया था। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा—"मां, अब मेरी बारी है।" उनकी आवाज़ भर्रा गई थी।

उसी क्षण उन्हें लगा कि मां की उंगली में हल्की-सी हरकत हुई है। वे चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर दोबारा महसूस करने की कोशिश की। शायद यह उनका भ्रम था, लेकिन उस भ्रम ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उन्हें लगा कि मां सब कुछ महसूस कर रही हैं, बस बोल नहीं पा रहीं। इस विश्वास ने उनकी सेवा में और भी गहराई ला दी।

दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन एक जैसा था, फिर भी हर दिन अलग लगता था। मां की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन घर के हर सदस्य के भीतर कुछ न कुछ बदल रहा था। वे सब धीरे-धीरे उस सच्चाई के करीब जा रहे थे, जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है।

एक रात अचानक बिजली चली गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां हिल रही थीं और घर के अंदर अंधेरा फैल गया था। शर्मा जी मोमबत्ती जलाकर मां के कमरे में पहुंचे। उस हल्की रोशनी में सब कुछ और भी शांत और गंभीर लग रहा था। उन्होंने मां का हाथ थामा। उसी क्षण उन्हें साफ महसूस हुआ—मां ने उनकी उंगली को कसकर पकड़ लिया।

उनकी सांस रुक-सी गई। "मां?" उनकी आवाज कांप रही थी। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने ध्यान से देखा—मां की पलकों में हल्की-सी हरकत हुई। उन्होंने मोमबत्ती को थोड़ा पास किया। मां के होंठ भी हल्के-से हिले, जैसे कोई शब्द बनने की कोशिश कर रहा हो।

शर्मा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। "मां, मैं यहीं हूं कुछ कहना है?" उनकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। उसी पल मां की आंखों के कोने से एक आंसू निकलकर धीरे-धीरे गाल पर बह गया। यह आंसू जैसे वर्षों की सारी भावनाओं को समेटे हुए था।

उन्होंने तुरंत सरला को आवाज दी। वह दौड़ती हुई आई। शर्मा जी ने धीमे स्वर में कहा—"इन्होंने मेरी उंगली पकड़ी" दोनों उस क्षण को जैसे थाम लेना चाहते थे। तभी मां की सांसें थोड़ी तेज हुईं। उनके मुंह से बहुत हल्की, लगभग हवा जैसी आवाज निकली—"स्ससर" बस इतना ही। शब्द अधूरा था, लेकिन भाव पूरा था। शायद वह सरला को बुला रही थीं, शायद कुछ कहना चाहती थीं, या शायद सिर्फ यह जताना चाहती थीं कि वे जा रही हैं। इसके बाद उनकी सांसें धीरे-धीरे शांत हो गईं। कमरे में एक गहरी शांति छा गई, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। सरला रो पड़ी। "मेरा नाम ही पूरा नहीं बोल पाईं" उसकी सिसकियों में दर्द था। लेकिन उस अधूरे शब्द में भी एक अपनापन था, एक अंतिम स्पर्श, जो हमेशा के लिए याद बन गया।

शर्मा जी मां के पास बैठे रहे। उनके चेहरे पर अब वही शांति थी, लेकिन इस बार उसमें दूरी नहीं थी। उन्हें अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जाते-जाते मां ने उनका हाथ थाम लिया था। वह स्पर्श ही उनका अंतिम संवाद था—अधूरा शब्द, लेकिन पूरा विदा।

बंगाल में अराजकता का साया

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को जिस तरह घेराव कर घंटों तक बंधक बनाए रखा गया, उससे कानून के शासन को अराजकता की सीधी चुनौती मिलती हुई दिखी। यह मामला इतना गंभीर था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने दखल दिया और देर रात घटना का जायजा लेने के साथ ही बंगाल सरकार के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियां कीं।

उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने जांच एनआइए को सौंप दी है। तीन महिला अफसरों समेत सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने वाले कुछ राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

आश्चर्य इस पर है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई व्यवस्था को चुनौती देने वाली अराजकता का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि लोग इसलिए नाराज थे, क्योंकि कथित तौर पर वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए थे। यदि एक क्षण के लिए इसे सही मान लें तो क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो वह खुली अराजकता करेगा? ममता बनर्जी ने मालदा की घटना से पल्ला झाड़ने की जो कोशिश की, उस पर हैरानी नहीं। वह हर बार ऐसा ही करती हैं।

बंगाल में एसआईआर के खिलाफ असें से अराजक प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यह दुष्प्रचार कर रही है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य उसके समर्थकों के वोट काटना है। वे यह कुप्रचार तभी से कर रही हैं, जबसे बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ। एसआईआर के खिलाफ उनकी ओर से बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उलटे-सीधे आरोपों के साथ चुनाव आयोग को बदनाम किया गया।

शीर्ष न्यायालय ने उनके आरोप निराधार पाकर एसआईआर जारी रखने के आदेश दिए। इसके बाद ममता प्रशासन ने चुनाव आयोग का असहयोग करना शुरू कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में कराने का अभूतपूर्व आदेश दिया। यह आदेश यही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का राज्य के शासन-प्रशासन पर भरोसा नहीं।

आखिर ममता सरकार चुनाव आयोग को उसका संवैधानिक काम क्यों नहीं करने दे रही है और वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट उसके काम में कोई खोट नहीं देख रहा है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को उचित मान रहा है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए यह भी माहौल बना रही है कि वह वही कर रहा है, जो केंद्र सरकार चाह रही है। यह वही आरोप है, जो बिहार में एसआईआर के समय खूब उछाला गया, पर इससे विपक्षी दलों का नुकसान ही हुआ।

यदि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सही पा रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस पर केंद्र सरकार हावी हो गई है। बिहार के बाद बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इन सभी राज्यों में वोटरों के नाम कटे हैं, पर वे उनके हैं, जो अन्यत्र चले गए या फिर जिनका निधन हो गया अथवा जिनका नाम वोटर लिस्ट में दो-दो बार था।

न जाने क्यों तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि लंबे अंतराल बाद एसआईआर होगा तो वोटर लिस्ट में कुछ नाम जुड़ेंगे तो कुछ उससे कटेंगे? एसआईआर कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी हो रहा है, पर उसका सबसे अधिक विरोध बंगाल में इसलिए हो रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक तत्व उसके विरोध में हद से ज्यादा आगे चले गए हैं। लगता है तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है, ताकि वह अपने 15 वर्षों के शासन के खिलाफ उभरी एंटी इनकंबेंसी से लोगों का ध्यान हटा सके।

ममता बनर्जी वाम दलों को परिवर्तन के नारे के साथ बेदखल कर सत्ता में आई थीं, पर धीरे-धीरे उन्होंने वही तौर-तरीके अपना लिए जो वाम दलों ने अपना रखे थे। यह एक विडंबना है कि बंगाल में जो भी सत्ता में आता है, वह अराजकता का सहारा लेने लगता है। इसके चलते अन्य दलों के बाहुबली सत्ताधारी दल में शामिल हो जाते हैं। चूंकि बंगाल के सत्तारूढ़ दल अराजकता का सहारा लेते हैं, इसलिए यहां चुनाव के पहले भी हिंसा होती है, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी। इस बार भी आशंका है कि पहले की तरह इस बार भी यहां हिंसा हो सकती है। ध्यान रहे कि पिछले चुनावों के बाद की हिंसा इतनी भयानक थी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसकी जांच सीबीआइ से कराने का फैसला लिया था। इस बार चुनावी हिंसा की आशंका के चलते ही चुनाव आयोग ने यह असाधारण फैसला लिया कि राज्य में चुनाव बाद भी अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे।

चूंकि चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा होती ही है, इसलिए यहां के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। ये सवाल इसलिए अधिक उठते हैं, क्योंकि राज्य में नौकरशाही का राजनीतिकरण हो चुका है। इसी कारण चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी, गृह सचिव समेत तमाम अधिकारियों का तबादला किया। बंगाल की कानून व्यवस्था सदैव सवालों के घेरे में रहती है। इसका कारण यही है कि ममता बनर्जी ने उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणियां की हों, पर यदि ममता फिर से सत्ता में लौटती हैं तो कानून व्यवस्था जस की तस रहने की ही आशंका है।

इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और चुनाव आयोग की सक्रियता से बंगाल पुलिस प्रशासन का रवैया बदलेगा।

अभियान

हनुमान चालीसा पाठ के रहस्य और सफल साधना के नियम

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाने का मार्ग मानी जाती है। इसी परंपरा में हनुमान चालीसा का विशेष स्थान है, जो न केवल एक स्तुति है बल्कि साधना का एक प्रभावशाली सूत्र भी है। मान्यता है कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को पवनपुत्र हनुमान का जन्म हुआ था, जिसे हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। यह दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति के जागरण का अवसर होता है। इस दिन विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके सभी कष्ट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं।

हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धता से जुड़ा हुआ एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है, तो वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है। यही कारण है कि इसे संकटमोचन स्तोत्र भी कहा जाता है। जीवन में आने वाले भय, चिंता, नकारात्मक विचार और अदृश्य बाधाएं इस पाठ के नियमित अभ्यास से धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं।

इस साधना का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है शुद्धता। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और विचारों की भी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति चालीसा का पाठ कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मकता भरी हुई है, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पाठ से पहले मन को शांत करना, कुछ क्षण ध्यान लगाना और अपने भीतर सकारात्मक भाव जगाना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया साधारण लग सकती है, लेकिन यही वह आधार है, जिस पर पूरी साधना टिकी होती है।

दूसरा महत्वपूर्ण नियम है संयम। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे अपने जीवन में कुछ अनुशासन अपनाने होते हैं। मांस और मदिरा का त्याग, सात्विक भोजन का सेवन और जीवन में सादगी का पालन इस साधना को प्रभावशाली बनाते हैं। यह केवल धार्मिक नियम नहीं हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए भी आवश्यक हैं। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तभी व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ भक्ति कर पाता है।

हनुमान चालीसा का पाठ दिन में तीन बार करना विशेष लाभदायक माना गया है—सुबह, दोपहर और शाम। सुबह का पाठ दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है, दोपहर का पाठ मन को स्थिर करता है और शाम का पाठ पूरे दिन की थकान और तनाव को दूर करता है। यह नियमितता व्यक्ति के जीवन में एक लय पैदा करती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

इस पाठ का एक और गहरा पहलू है भावना। केवल शब्दों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन शब्दों के अर्थ और भाव को समझना भी जरूरी है। जब हम "जय हनुमान ज्ञान गुन सागर" कहते हैं, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम ज्ञान और गुणों के महासागर को प्रणाम कर रहे हैं। जब हम "नासै रोग हरै सब पीरा" का उच्चारण करते हैं, तो हमारे भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यही विश्वास इस पाठ को प्रभावशाली बनाता है।

हनुमान चालीसा में वर्णित प्रत्येक चौपाई एक विशेष ऊर्जा को दर्शाती है। इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, भक्ति और सेवा भावना का वर्णन है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और समर्पण में होती है। जब व्यक्ति इस भाव को अपने जीवन में उतारता है, तो उसका व्यक्तित्व स्वतः ही निखरने लगता है।

इस साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे किसी विशेष अवसर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हनुमान जयंती जैसे पर्व पर इसका विशेष महत्व जरूर है, लेकिन इसका नियमित अभ्यास ही वास्तविक फल देता है। जब व्यक्ति इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है, तो वह धीरे-धीरे अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक सहजता से कर पाता है।

कई लोग यह मानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ केवल धार्मिक लाभ देता है, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। यह व्यक्ति को भयमुक्त बनाता है, उसके भीतर साहस और धैर्य का संचार करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, तो वह अपने जीवन की चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे समस्याएं कम और समाधान अधिक दिखाई देने लगते हैं।

इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य अधूरा होता है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसे एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, जो उसे हर परिस्थिति में संभालती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता।

अंततः, हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे-धीरे पूर्ण होने लगती हैं। सही विधि, शुद्ध भावना और नियमित अभ्यास के साथ किया गया यह पाठ न केवल हमारे जीवन के कष्टों को दूर करता है, बल्कि हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पंजाब मेरी पहचान और जिम्मेदारी, सियासी विवाद के बीच राघव का तीखा जवाब

आम आदमी पार्टी के भीतर उभरे ताजा राजनीतिक विवाद ने अब खुलकर एक नए मोड़ ले लिया है, जहां पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक Raghav Chadha ने अपने ही संगठन पर लगे आरोपों का न केवल जवाब दिया है, बल्कि अपने बयान के जरिए एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी दिया है। पार्टी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उन्होंने संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया, राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से विस्तार से अपनी बात रखते हुए इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उनका घर, उनका कर्तव्य, उनकी मिट्टी और उनकी आत्मा है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब Aam Aadmi Party ने आंतरिक स्तर पर यह संकेत दिया कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उप-नेता पद से हटा दिया गया, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इस फैसले को लेकर न केवल पार्टी के भीतर बल्कि बाहरी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गईं। राघव चड्ढा ने इसे केवल एक पद से हटाए जाने का मामला नहीं माना, बल्कि इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया।

अपने बयान में राघव चड्ढा ने विस्तार से उन मुद्दों का उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने संसद में उठाया था। उन्होंने Nankana Sahib कॉरिडोर की वकालत करने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी की मांग करने, पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर की समस्या को उजागर करने और शहीद Bhagat Singh को भारत रत्न देने की सिफारिश करने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को गिनाया। उनका कहना था कि ये सभी मुद्दे पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इन पर संसद में गंभीरता से आवाज उठाई है।

राघव चड्ढा ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए यह भी कहा कि उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, वह स्वतःस्फूर्त नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही तरह की भाषा, एक जैसे शब्द और एक जैसे आरोप अलग-अलग लोगों द्वारा दोहराए जा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह सब किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरू में उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि बार-बार झूठ दोहराने से कुछ लोग उस पर विश्वास करने लग सकते हैं, तब उन्होंने अपनी बात रखने का निर्णय लिया।

इस पूरे घटनाक्रम ने Aam Aadmi Party के अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने राघव चड्ढा के खिलाफ खुलकर बयान दिए हैं और उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने समझौता कर लिया है तथा Narendra Modi से डरते हैं। इन आरोपों ने विवाद को और अधिक तीखा बना दिया है, क्योंकि अब यह केवल कार्यशैली का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि व्यक्तिगत और वैचारिक मतभेदों का रूप लेता जा रहा है।

राघव चड्ढा ने इन आरोपों का भी कड़ा खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी संसद से वॉकआउट करने से इनकार नहीं किया और न ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पीछे हटे। उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि यह पूरा विवाद अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया गया है, ताकि उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी के भीतर चल रहे व्यापक अंतर्विरोधों का संकेत हो सकता है। पंजाब, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां की राजनीति और वहां के मुद्दों को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद उभरना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में राघव चड्ढा का यह बयान कि "यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है", आने वाले समय में और बड़े खुलासों या राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा करता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आज की राजनीति में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां नेता सीधे जनता से संवाद कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। राघव चड्ढा ने भी इसी माध्यम का उपयोग करते हुए न केवल अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा को भी स्पष्ट किया।

फिलहाल यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में इसके और गहराने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस स्थिति को कैसे संभालता है और क्या यह विवाद किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार करेगा। लेकिन इतना तय है कि राघव चड्ढा के इस बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो आने वाले समय में और तेज हो सकती है।

ड्यूटी के दौरान दर्दनाक हादसे, कुपवाड़ा से बंगाल सीमा तक जवानों की मौत ने उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र Kupwara से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेना के एक जवान की अपनी ही सर्विस गन से चली गोली के कारण मौत हो गई। यह हादसा कुपवाड़ा जिले के कलामाबाद इलाके में स्थित एक सैन्य शिविर में हुआ, जिसने सुरक्षा बलों के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानसिक दबाव जैसे मुद्दों पर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। मृतक जवान की पहचान 24 वर्षीय जगदीप के रूप में हुई है, जो ड्यूटी के दौरान इस दुर्घटना का शिकार हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को शिविर के भीतर अचानक उनकी सर्विस गन से गोली चल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवानों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए हंडवारा के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत को देखते हुए उन्हें 92 बेस अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना ने पूरे सैन्य परिसर को स्तब्ध कर दिया और जवानों के बीच शोक की लहर दौड़ गई।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल लगातार सतर्कता के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर इसे एक दुर्घटना माना जा रहा है, लेकिन सेना के अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि गोली चलने के पीछे तकनीकी चूक थी या किसी अन्य कारण ने इसे जन्म दिया। सेना के भीतर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त नियम होते हैं, ऐसे में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है।

इसी तरह की एक और घटना पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सामने आई, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी Border Security Force के एक जवान की अपनी ही राइफल से चली गोली के कारण मौत हो गई। यह घटना नदिया जिले के मुरुतिया क्षेत्र स्थित रानीनगर शिविर में हुई, जहां 34 वर्षीय जवान वैभव अन्ना मंडले ड्यूटी पर तैनात थे। वह महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले थे और बीएसएफ की 11वीं बटालियन में कार्यरत थे।

बताया गया कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी राइफल से गोली चली, जो सीधे उनके जबड़े में जा लगी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल करीमपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण, जैसे आत्महत्या या मानसिक तनाव, जिम्मेदार था।

स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरुतिया पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली चलने की वास्तविक वजह क्या थी। जानकारी के अनुसार, वैभव पिछले पांच दिनों से लगातार ड्यूटी पर तैनात थे, जिससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अत्यधिक काम का दबाव या थकान इस घटना का कारण तो नहीं बनी।

दोनों घटनाएं यह संकेत देती हैं कि सुरक्षा बलों में तैनात जवानों को न केवल बाहरी खतरों से जूझना पड़ता है, बल्कि कई बार आंतरिक चुनौतियां भी उनके सामने होती हैं। लगातार तनाव, कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी, परिवार से दूर रहना और जिम्मेदारियों का बोझ कई बार मानसिक दबाव को बढ़ा देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जवानों को समय-समय पर परामर्श और सहयोग मिल सके।

इसके साथ ही हथियारों के सुरक्षित संचालन और रखरखाव को लेकर भी सख्ती बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि सेना और अर्धसैनिक बलों में इसके लिए पहले से ही कड़े नियम लागू हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश अभी भी मौजूद है।

शक, अपमान और रिश्तों की दरार ने ली खौफनाक शक्ल फरीदाबाद में दो महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश

हरियाणा के Faridabad के डबुआ कॉलोनी इलाके से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में पनप रहे तनाव और अविश्वास के खतरनाक परिणामों को भी उजागर कर दिया है। एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने अपनी ही दो जेठानियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और उन्हें तत्काल उपचार के लिए दिल्ली के Safdarjung Hospital में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना 3 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है, जब डबुआ कॉलोनी निवासी सीमा और मीना अपने घर पर मौजूद थीं। उसी दौरान उनकी देवरानी पिंकी वहां पहुंची। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा—दोनों जेठानियों ने उसका स्वागत किया, उसे चाय पिलाई और सामान्य बातचीत होती रही। लेकिन इस सामान्य माहौल के पीछे एक भयावह साजिश पल रही थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पिंकी अपने साथ एक बैग लेकर आई थी, जिसे उसने चुपके से बाथरूम

में रख दिया था, और मौके का इंतजार करने लगी।

शाम करीब 5 बजे जब सीमा और मीना घर की छत पर खड़ी थीं, तभी पिंकी बाथरूम से एक बाल्टी में पेट्रोल भरकर बाहर आई। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पातीं, उसने अचानक उन पर पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस की तीली जलाकर उनकी ओर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में आग की लपटों ने दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की। पड़ोसियों की तत्परता के कारण ही दोनों महिलाओं को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका, वरना स्थिति और भी भयावह हो सकती थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपी महिला पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया और शनिवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल करते हुए जो कारण बताया, वह रिश्तों में गहराते अविश्वास और मानसिक तनाव की कहानी बयां करता है। पिंकी के अनुसार, उसकी दोनों जेठानियां अक्सर उसके चरित्र पर संदेह करती थीं और उस पर लगातार आरोप लगाती रहती थीं। इसी अपमान और मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर उसने इस खौफनाक कदम को उठाने का फैसला किया।

जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार के अनुसार, आरोपी महिला अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी है और उसने B.Sc. व B.Ed. जैसी डिग्रियां हासिल की हैं। वह एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी, जिससे यह घटना और भी चौंकाने वाली बन जाती है। एक शिक्षित महिला द्वारा इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम देना यह दर्शाता है कि मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद किस हद तक किसी व्यक्ति को अंधे गुस्से की ओर धकेल सकते हैं।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसने पेट्रोल कहां से खरीदा और क्या इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। पारिवारिक रिश्तों में यदि संवाद और विश्वास की कमी हो जाए, तो छोटे-छोटे विवाद भी खतरनाक रूप ले सकते हैं। इस मामले में भी यदि समय रहते आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जाती, तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवार के भीतर होने वाले मानसिक दबाव और आरोप-प्रत्यारोप कई बार व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं, जिसका परिणाम इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आता है।

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि जिस तरह से एक पारिवारिक विवाद ने इतनी भयावह शक्ल ले ली, वह बेहद चिंताजनक है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

फिलहाल दोनों पीड़ित महिलाओं का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में विश्वास और संवाद की कितनी अहम भूमिका होती है, और उनकी कमी किस तरह विनाशकारी परिणाम ला सकती है।

सूरत में एचएसआरपी नंबर प्लेट मामले में एजेंटों की लूट: सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के आरटीओ अधिकारी सूरत को दलालवाड़ी की दुकान समझते प्रतीत होते हैं। क्योंकि अब तक एचएसआरपी नंबर प्लेट बनाने का काम आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत आता था। दोपहिया वाहनों के लिए 140 रुपये प्रति जोड़ी और चार पहिया वाहनों के लिए 450 रुपये प्रति जोड़ी की दर से नंबर प्लेट जनता को मिलती थी। अब आरटीओ ने यह काम बंद कर दिया है और एजेंटों को एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट बनाने की अनुमति दे दी है। ऐसा लगता है मानो एजेंट महंगाई से लड़ रहे हों और दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों से क्रमशः 900 रुपये और 1500 रुपये वसूल कर उन्हें लूट रहे हों? फिर सवाल उठता है कि जब सरकार अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से जनता को एचएसआरपी नंबर प्लेट की सरकारी कीमतें बताती है, तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाहन चालकों को उन सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित कीमतों का कोई लाभ नहीं मिलता। मनमानी कीमतें वसूल कर एजेंट सरकार की नाकामी का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आरटीओ समेत पूरी सरकारी व्यवस्था इस मामले में चुप बैठी है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि आरटीओ द्वारा जारी आदेश कि दोपहिया वाहन शोरूम में प्रत्येक वाहन पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट होनी चाहिए, एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है: क्या आरटीओ और नंबर प्लेट बनाने वाले गांधी वैद्य के सहयोगी की तरह काम नहीं कर रहे हैं?

नकली कस्टम अफसर बनकर दिनदहाड़े वारदात, पटना में 15 किलो सोने की बड़ी लूट

बिहार की राजधानी Patna में अपराधियों ने बेहद शातिर तरीके से एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के एक स्वर्ण व्यापारी को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर लगभग 15 किलो सोना लूट लिया और फरार हो गए। यह घटना न केवल सुनियोजित प्रतीत होती है, बल्कि इसमें अपराधियों की पेशेवर तैयारी और पूर्व जानकारी का भी स्पष्ट संकेत मिलता है।

मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के राजकोट निवासी महेश मामतोरा नामक व्यापारी व्यापारिक कार्य से पटना पहुंचे थे। वह अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस से Danapur Railway Station पर उतरे और शहर के बाकरगंज इलाके में जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। लेकिन स्टेशन से निकलते ही वह अपराधियों के निशाने पर आ गए। फ्लाईओवर के पास बाइक सवार कुछ लोगों ने अचानक उन्हें रोका, जबरन ऑटो से उतारा और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए एक दूसरी गाड़ी में बैठा लिया।

व्यापारी के अनुसार, बदमाशों ने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में बैठाने के बाद उन्होंने उनके हाथ बांध दिए और मुंह बंद कर दिया, ताकि वह किसी से मदद न मांग सकें। इस दौरान अपराधी लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और यह भी कहते सुने गए कि "आपकी जानकारी सही निकली, हम पांच दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे।" इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि अपराधियों को व्यापारी के आने और उसके पास मौजूद सोने की खेप की पहले से ही पूरी जानकारी थी।

गाड़ी में करीब 10 से 15 मिनट तक घुमाने के बाद बदमाशों ने व्यापारी के पास मौजूद सोने की पूरी खेप, मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। इसके बाद उसे शहर से दूर Naubatpur नहर के पास एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया और फरार हो गए। जिस वाहन में उसे छोड़ा गया, वह भी चोरी की बताई जा रही है, जिससे यह साफ होता है कि अपराधियों ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस वारदात की योजना बनाई थी। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उसके पास लगभग 15 से 20 किलो सोने का सामान था, जिसे वह पटना के विभिन्न कारोबारियों को देने के लिए लाया था। यह भी सामने आया है कि शहर में पहले से ही उनके व्यापारिक संपर्क थे, जिससे यह शक और गहरा जाता है कि कहीं अंदरूनी जानकारी के आधार पर ही इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। व्यापारी ने यह भी बताया कि बदमाशों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह पूरी तरह भ्रमित हो गया और उन्हें असली अधिकारी समझ बैठा।

घटना के बाद किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से व्यापारी ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस आसपास के इलाकों और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की बौछार: मतदाताओं को लुभाने का राजनीतिक खेल और इसके प्रश्न

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में चुनाव का मौसम नजदीक आने के साथ ही सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल मतदाताओं को लुभाने के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं। इस दौरान मुफ्त उपहार बांटने का चलन भी बढ़ रहा है। कुछ समय पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये जमा किए थे। इसी तरह पंजाब सरकार ने अब "मुख्यमंत्री मावन-ध्यान सत्कार योजना" को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। यह 2022 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया एक बड़ा वादा था। यह वादा अब अगले चुनाव चक्र से एक साल पहले लागू किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राज्य सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को यह "मुफ्त उपहार" दिया है?

कुछ साल पहले, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने चुनाव से पहले "लाडली बहन" योजना पेश की और भारी बहुमत से जीत हासिल की। तब से, विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने का एक नया फॉर्मूला खोज निकाला है। इसके बाद, महाराष्ट्र से लेकर जहां भी चुनाव होते हैं, सत्ताधारी से लेकर विपक्षी दल तक, सभी तरह-तरह के मुफ्त पैकेज देने लगे हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 'रेवाड़ी' संस्कृति पर नाराजगी जताई है।

लेकिन राजनीतिक दलों और सरकारों में कोई सुधार नहीं हुआ है। और यह गतिविधि अभी भी जारी है। अब पंजाब भी इसमें शामिल हो गया है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री रेवड़ी संस्कृति की बात करके विपक्ष का मजाक उड़ाते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी ने बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक के चुनावों में रेवड़ी बांटकर सत्ता हासिल की है। कहा जाता है कि अगर मैं करूं तो ठीक है, और अगर दूसरे करें तो बुरा है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में सरकारी योजनाओं को जल्दबाजी में लागू करने के तरीके की बार-बार आलोचना की गई है और सवाल उठाए गए हैं। मुफ्त उपहार बांटने का यह चलन सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहा है। पिछले महीने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कई राज्य सरकारें पहले से ही कर्ज में डूबी हैं, तो वे मुफ्त उपहार क्यों बांट रही हैं?

यह हमारे लोकतांत्रिक देश की सच्चाई है, जहां मतदाताओं को खरीदा जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं, और अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करने वाला वर्ग भी इसकी परवाह नहीं करता, तो बाकी लोगों का क्या?

शराब के चक्कर में खुला राज, चोरी की बाइक और फर्जी नंबर प्लेट का पर्दाफाश

मध्य प्रदेश के Jabalpur से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो यह साबित करता है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक छोटी सी गलती पूरी साजिश को उजागर कर देती है। यहां एक युवक की शराब की लत और उसकी लापरवाही ने उसे सीधे पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे इस शख्स की 'होशियारी' उस वक्त खत्म हो गई, जब यातायात पुलिस की पैनी नजर उस पर पड़ गई।

शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंजना तिवारी के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी अभियान के तहत गढ़ा क्षेत्र में पुलिस की टीम महानंदा शराब दुकान के पास 'नो पार्किंग' में खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही थी। तभी पुलिसकर्मियों की नजर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर पड़ी, जो पहली नजर में सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट ने पूरी कहानी बदल दी।

नंबर प्लेट पर MP 20 MX 737 लिखा हुआ था, लेकिन ध्यान से देखने पर पुलिस को उसमें एक अंक की कमी नजर आई। यही छोटी सी चूक आरोपी पर भारी पड़ गई। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तुरंत बाइक की गहराई से जांच शुरू कर दी। निरीक्षक इंदिरा ठाकुर और सूबेदार मनीष पयासी की टीम ने बाइक के चेसिस नंबर को नोट किया और उसे डेटाबेस से मिलाया। जांच के दौरान सामने आया कि यह मोटरसाइकिल असल में चोरी की है और इसकी रिपोर्ट दो साल पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी। जब पुलिस ने असली मालिक से संपर्क किया, तो उसने पुष्टि की कि उसकी बाइक दो साल पहले चोरी हो गई थी और इसकी एफआईआर रामपुर चौकी में दर्ज है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर मौजूद युवक को हिरासत में ले लिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह इसे पूरी तरह सही तरीके से तैयार नहीं कर पाया, जिससे उसकी पोल खुल गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुद को बचाने की कोशिश में एक कहानी गढ़ी। उसने बताया कि उसने यह बाइक 'राजेश' नाम के एक व्यक्ति से करीब 20 हजार रुपये में खरीदी थी। हालांकि जब पुलिस ने उससे उस व्यक्ति का पूरा नाम, पता या कोई दस्तावेज मांगा, तो वह कुछ भी नहीं बता पाया। उसके पास बाइक से संबंधित कोई कागजात भी नहीं थे, जिससे उसकी कहानी और भी कमजोर साबित हो गई। अब आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है और पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। चोरी की बाइक का इस्तेमाल और फर्जी नंबर प्लेट लगाना उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य के रूप में सामने आया है।

सूरत नगर निगम चुनाव में AAP का बड़ा दांव 75 उम्मीदवारों की सूची से तेज हुई सियासी जंग

सूरत। गुजरात के सूरत नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। 120 सीटों वाले सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए Aam Aadmi Party ने बड़ा दांव खेलते हुए अपने 75 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार केवल विपक्ष की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सीधे सत्ता हासिल करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है।

पार्टी द्वारा जारी की गई इस सूची में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन साफ दिखाई देता है। Payal Sakariya, Rachna Hirpara और Mahesh Andhan जैसे नेताओं को फिर से मौका दिया गया है, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में विपक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी पहचान बनाई थी। इसके साथ ही पार्टी ने कई नए और युवा चेहरों को भी टिकट देकर यह संकेत दिया है कि वह जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और नए मतदाताओं को आकर्षित करने की दिशा में गंभीर है।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में AAP ने 27 सीटें जीतकर सूरत की राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस चुनाव में Bharatiya Janata Party ने बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में इस बार का मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है, जहां AAP खुद को एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

पार्टी के राज्य संगठन महासचिव Manoj Sorathiya ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि सूरत की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए दावा किया कि AAP एक ईमानदार और पारदर्शी शासन का विकल्प प्रस्तुत कर रही है। उनके अनुसार, पार्टी का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा, जैसा कि दिल्ली और पंजाब में देखने को मिला है।

उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सूची में पाटीदार, ओबीसी, आदिवासी और अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा शिक्षित युवाओं, वकीलों और समाजसेवियों को टिकट देकर AAP ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह केवल पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नए विचारों और नेतृत्व को भी आगे लाना चाहती है।

वार्डवार उम्मीदवारों की सूची में कई नाम ऐसे हैं, जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं और जनता के बीच उनकी पहचान है। पार्टी को उम्मीद है कि इन उम्मीदवारों के जरिए वह बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगी और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AAP की यह रणनीति सूरत की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बना सकती है। जहां एक ओर भाजपा अपने मजबूत संगठन और पिछले प्रदर्शन के दम पर चुनाव में उतर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। ऐसे में AAP का यह आक्रामक कदम चुनावी समीकरणों को बदल सकता है।

पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि वह जल्द ही बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके साथ ही जनसंपर्क अभियान, रैलियां और अन्य चुनावी गतिविधियां भी तेज की जाएंगी।

कुल मिलाकर, सूरत नगर निगम चुनाव इस बार केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी बनता जा रहा है। AAP की यह पहली सूची इस बात का प्रमाण है कि पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है और किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं और सूरत की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है।

बंगाल चुनाव में BJP का मेगा दांव, 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतरी मैदान में

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अब तेजी से चढ़ता जा रहा है और इसी बीच Bharatiya Janata Party ने चुनावी रण में बड़ा दांव चलते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में देश के शीर्ष नेताओं से लेकर चर्चित चेहरों तक को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लड़ रही है और कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है।

स्टार प्रचारकों की इस सूची में प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah, रक्षा मंत्री Rajnath Singh और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath जैसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेता भी इस सूची का हिस्सा हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार को धार देंगे।

भाजपा ने जिन अन्य प्रमुख चेहरों को इस सूची में शामिल किया है, उनमें Nitin Gadkari, J. P. Nadda, Dharmendra Pradhan, Himanta Biswa Sarma और Shivraj Singh Chouhan जैसे नाम शामिल हैं। वहीं फिल्म और खेल जगत से जुड़े चेहरों को भी प्रचार में उतारा गया है, जिनमें Mithun Chakraborty, Leander Paes, Hema Malini और Kangana Ranaut प्रमुख हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा का यह कदम चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसमें पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को राज्य स्तर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है, ताकि अधिकतम मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा सके।

चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होना है, जबकि 4 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं।

चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूचबिहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की Mamata Banerjee सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी ने अपने भाषण में विकास, कानून-व्यवस्था और केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भाजपा के अलावा अन्य दल भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं हैं, लेकिन पार्टी की ओर से इतने बड़े पैमाने पर स्टार प्रचारकों की तैनाती ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और चुनाव प्रचार को गति मिलेगी। इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़ है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता और आक्रामक प्रचार अभियान के जरिए वह मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल रहेगी।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा की स्टार प्रचारकों की यह लंबी सूची इस बात का संकेत है कि पार्टी इस चुनाव को किसी भी हाल में जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे प्रचार तेज होगा, वैसे-वैसे चुनावी मुकाबला और अधिक रोमांचक होता जाएगा।

तापी में बढ़ती जलकुंभी से गहराया जल संकट, सफाई पर उठे सवाल

सूरत शहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही एक बार फिर तापी नदी में जलकुंभी की समस्या तेजी से विकराल रूप लेने लगी है, जिससे न केवल नदी की स्वच्छता बल्कि शहर की पेयजल व्यवस्था पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। तापी नदी सूरत के लिए जीवनरेखा मानी जाती है और इसी नदी से बड़ी मात्रा में पानी शहरवासियों को सप्लाई किया जाता है, ऐसे में नदी में बढ़ती जलकुंभी, गाद और प्रदूषण की स्थिति प्रशासन की चिंता को बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी बेचैनी पैदा कर रही है। जलकुंभी का अत्यधिक फैलाव नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहा है और कई स्थानों पर पानी का ठहराव साफ देखा जा सकता है, जो आगे चलकर जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। नगर निगम द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए वियर क्षेत्र में डिवाइडर मशीनें लगाकर जलकुंभी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई इलाकों में जलकुंभी के बड़े-बड़े गुच्छे एकत्रित हो गए हैं, जिससे साफ-सफाई के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मशीनें या तो पर्याप्त संख्या में नहीं हैं या फिर उनका संचालन प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। जलकुंभी के कारण पानी का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, जिससे गंदगी और अपशिष्ट भी वहीं जमा होने लगते हैं और यह स्थिति जल स्रोत को धीरे-धीरे दूषित करने लगती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, जलकुंभी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। इससे जलीय जीवों के जीवन पर भी खतरा उत्पन्न होता है और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जलकुंभी के अत्यधिक फैलाव के कारण नगर निगम के वॉटर वर्क्स प्रभावित हुए हैं और पानी की सप्लाई में बाधा आई है। इसके बावजूद यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। स्थिति को और चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि कुछ स्थानों से नदी में गंदा पानी और औद्योगिक अपशिष्ट मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है, तो यह समस्या केवल जलकुंभी तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि यह एक व्यापक प्रदूषण संकट का रूप ले लेती है। जलकुंभी ऐसे प्रदूषित पानी में तेजी से बढ़ती है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि नदी की स्वच्छता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह स्थिति शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है।

पिछले मानसून के दौरान कॉजवे के ओवरफ्लो होने से जलकुंभी का फैलाव कुछ समय के लिए कम हो गया था, क्योंकि तेज बहाव में यह पौधा बहकर आगे निकल गया था। लेकिन अब जब नदी का प्रवाह सामान्य है, तो जलकुंभी फिर से तेजी से फैलने लगी है। यह हर साल होने वाली एक चक्रीय समस्या बन चुकी है, जिसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हर बार अस्थायी उपाय किए जाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक योजना की कमी साफ दिखाई देती है।

स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता। लोगों को डर है कि यदि जल्द ही व्यापक स्तर पर सफाई अभियान नहीं चलाया गया, तो आने वाले समय में पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है और ऐसे समय में यदि जल स्रोत ही प्रभावित हो जाए, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। शहरवासियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग है कि नगर निगम को इस समस्या के समाधान के लिए एक ठोस और दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए। केवल मशीनों के सहारे सफाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नदी में गिरने वाले अपशिष्ट पर भी सख्ती से नियंत्रण करना होगा। साथ ही जलकुंभी के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए, ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

आपातकाल में सहारा बनी सेहत योजना लाखों परिवारों को मिला नया जीवन

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना आज के समय में स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत और भरोसेमंद आधार बनकर उभरी है, खासकर तब जब किसी परिवार पर अचानक मेडिकल इमरजेंसी का संकट टूट पड़ता है। दिल का दौरा, कैंसर, जन्म संबंधी जटिलताएं या अन्य गंभीर बीमारियां बिना किसी पूर्व चेतावनी के सामने आती हैं और ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती इलाज के खर्च को लेकर होती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाली यह योजना लाखों परिवारों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच तक लाने में अहम भूमिका निभा रही है।

मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में ज्यादातर गंभीर बीमारियां तब तक पकड़ में नहीं आतीं जब तक वे खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच जातीं। मोहाली जिला अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉ. ईशा अरोड़ा के अनुसार, अधिकांश मरीज अस्पताल तब पहुंचते हैं जब बीमारी पहले ही गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी होती है। इसका मुख्य कारण है लोगों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज करना और शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से न लेना। ऐसे में जब अचानक स्थिति बिगड़ती है तो परिवार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है—एक तरफ मरीज की जान बचाने की चिंता और दूसरी तरफ इलाज के भारी खर्च का दबाव। यही वह स्थिति है जहां मुख्यमंत्री सेहत योजना एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती है और इलाज को तुरंत शुरू करने में मदद करती है।

इस योजना के तहत अब तक 33 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा जा चुका है, जो अपने आप में इस पहल की सफलता का बड़ा प्रमाण है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 1,98,793 मामलों में मुफ्त इलाज की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसकी कुल लागत 3,30,01,32,533 रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ हर आयु वर्ग के लोगों को मिल रहा है, चाहे वह छोटे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग। दिल की सर्जरी, कैंसर का इलाज, डायलिसिस जैसी महंगी चिकित्सा सेवाएं अब आम लोगों के लिए भी सुलभ हो रही हैं।

भारत में स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा अब भी लोगों को अपनी जेब से ही उठाना पड़ता है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा सीधे लोगों की जेब से जाता है, जो कई बार परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। कई परिवार इलाज के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर अपनी संपत्ति तक बेच देते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसे प्रयास न केवल आर्थिक बोझ को कम करते हैं, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से भी राहत देते हैं। यह योजना इस सोच को बदलने में भी मदद कर रही है कि बेहतर इलाज केवल अमीरों के लिए ही संभव है।

सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि यह पहल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है। सरकार लगातार इस योजना के दायरे को बढ़ाने, अस्पतालों के नेटवर्क को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। इसका सीधा लाभ यह हो रहा है कि राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत सरल बनाई गई है। लाभार्थी को योजना में पंजीकरण के बाद एक हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसे अस्पताल में दिखाकर कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया ने मरीजों और उनके परिवारों के लिए इलाज को आसान बना दिया है, क्योंकि अब उन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले पैसे जमा कराने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे इलाज में होने वाली देरी को भी रोका जा सकता है, जो कई बार मरीज के लिए घातक साबित होती है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल योजना का लाभ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होना होगा। नियमित जांच, स्वस्थ जीवनशैली और समय पर इलाज जैसी आदतों को अपनाकर ही गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन इसके साथ-साथ जन जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। यह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहारा बनी है, बल्कि पूरे समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक नई उम्मीद भी जगा रही है। आने वाले समय में यदि इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया और इसके दायरे को विस्तारित किया गया, तो यह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

सेवा, संवेदना और समर्पण का अनूठा संगम बना जन्मदिन का उत्सव

सूरत शहर में एक ऐसा प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा सच्ची हो तो किसी भी व्यक्तिगत अवसर को समाज सेवा के बड़े अभियान में बदला जा सकता है। यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश सी. पाटिल ने अपने जन्मदिन को केवल एक निजी उत्सव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सेवा और संवेदना के उत्सव के रूप में मनाते हुए समाज के सामने एक मिसाल पेश की। इस खास मौके पर 500 से अधिक विधवा महिलाओं को खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई, जिससे न केवल जरूरतमंदों को राहत मिली बल्कि समाज में सहयोग और करुणा का संदेश भी मजबूती से गया।

अलथान टेनेमेंट स्थित संकल्प शॉपिंग सेंटर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आयोजन का माहौल पूरी तरह से सेवा भावना से ओतप्रोत नजर आया, जहां हर कोई किसी न किसी रूप में योगदान देने के लिए तत्पर दिखा। जिग्नेश पाटिल स्वयं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने हाथों से लाभार्थियों को खाद्य किट वितरित की। इस दौरान विधवा महिलाओं के चेहरों पर जो संतोष और खुशी झलक रही थी, वह इस पहल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण थी। कार्यक्रम में आए लोगों के लिए छाछ और नाश्ते की भी विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे पूरे आयोजन में अपनापन और सम्मान का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

कार्यक्रम के दौरान जिग्नेश पाटिल को गणेशभाई पी. सावंत और सागर जी. सावंत द्वारा पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए था जो समाज के कमजोर वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और शहर के कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया।

इस सेवा पहल की खास बात यह रही कि यह केवल एक दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे पांच दिनों तक विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिग्नेश पाटिल ने अपने जन्मदिन को एक अभियान का रूप देते हुए शहर के अलग-अलग स्कूलों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को नोटबुक, पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इससे उन बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद मिली, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि समाज उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालयों का भी दौरा किया, जहां बच्चों के साथ समय बिताकर उन्हें जरूरी वस्तुएं प्रदान की गईं। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि सेवा केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

जिग्नेश पाटिल ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उनके लिए जन्मदिन का वास्तविक अर्थ केक काटने या जश्न मनाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उन्होंने यह भी बताया कि यूथ फॉर गुजरात लगातार समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय है और भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। उनके इस दृष्टिकोण ने युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में जय भवानी क्रेडिट सोसाइटी के स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ कार्यक्रम की हर व्यवस्था को संभाला, जिससे यह आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सका। स्वयंसेवकों की मेहनत और टीमवर्क ने यह दिखाया कि जब लोग एकजुट होकर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है।

समाज के विभिन्न वर्गों से इस सेवा पहल को व्यापक सराहना मिल रही है। लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने खास अवसरों को समाज के हित में उपयोग करें। आज के दौर में जहां व्यक्तिगत उत्सव अक्सर दिखावे और भौतिकता तक सीमित हो जाते हैं, वहां जिग्नेश पाटिल की यह पहल एक नई दिशा दिखाती है।

यह आयोजन केवल एक जन्मदिन का जश्न नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख को समाज के साथ साझा करता है, तब वह सच्चे अर्थों में उत्सव बन जाता है। सूरत में आयोजित यह सेवा उत्सव आने वाले समय में कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और यह उम्मीद जगाएगा कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन के खास पलों को समाज के नाम कर दे, तो समाज में बदलाव की एक नई लहर पैदा हो सकती है।